



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 29 मार्च, 2006/8 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 29 मार्च, 2006

संख्या वि० स०—विधायन—गवर्न. बिल. 1-19/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पाईवेट विश्वविद्यालय (स्थापना

और विनियमन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्याक-7) जो आज दिनांक 29 मार्च, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/—

(जे० आर० गाज़टा),

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक,
2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा उनके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 है । और प्रारम्भ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

- (क) "प्रबन्ध बोर्ड" से धारा 20 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ख) "परिसर" (कैम्पस) से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;
- (ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;
- (घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यापक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;
- (ङ) "शासी निकाय" से धारा 19 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

- (च) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थानों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण अभिप्रेत है, जो प्रतिदेय नहीं है;
- (छ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;
- (झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय, या उसके महाविद्यालयों, संस्थानों और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ट) "परिसर(कैम्पस) बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो;
- (ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्धियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् आदि अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सरकार है;
- (ण) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (त) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (थ) "प्रायोजक निकाय" से किसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इच्छुक निकाय अभिप्रेत है; जोकि ;

- (i) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 1860 का 2 रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी; या
- (ii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी अन्य 1882 का 2 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास; या

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी; हो सकेगी;

- (द) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (ध) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (न) "छात्र" से विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित अनुसंधान उपाधि सहित किसी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (प) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;
- (फ) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और
- (न) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे ;

विश्वविद्यालय
के उद्देश्य ।

- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;
- (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना;
- (घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान और इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;
- (ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;
- (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

- (छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिग्रियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्रियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और
- (ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन रहते हुए परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र स्थापित करना ।

विश्वविद्यालय
की स्थापना
के लिए
प्रस्ताव
प्रस्तुत
करना और
उसका
मूल्यांकन।

4. (1) प्राइवेट सेक्टर में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन, जिसमें प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट अन्तर्विष्ट हो, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार को किया जाएगा ।

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) प्रायोजक निकाय का, उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, संविधान और उप-विधियों की प्रतियों के साथ, ब्यौरा;
- (ख) नवीनतम संपरीक्षित लेखों के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में जानकारी;
- (ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, अवस्थिति, प्रवर्तन के क्षेत्र और मुख्यालय;
- (घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (ङ) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के सम्बन्ध में न्यायोचित्य;
- (च) पाठ्यक्रमानुसार नामांकन लक्ष्यों सहित अध्ययन की प्रकृति और पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों द्वारा हाथ में लिए जाने वाले प्रस्तावित अनुसंधान और उनकी विकास लक्ष्यों तथा राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति सम्बद्धता और ऐसे कार्यक्रमों की पांच वर्षों में क्रमबद्धता;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित भूमि/भवनों और अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा और उन्हें अर्जित करने के साधन;
- (ज) विश्वविद्यालय के कृत्यशील होने से पूर्व किए जाने वाले परिसर (कैम्पस) विकास, जैसे कि भवनों का निर्माण, अवसंरचनात्मक सुविधाएं और अन्य सुख-सुविधाएं, उपस्कर का उपापन, इत्यादि के लिए योजनाओं के ब्यौरे तथा प्रथम

पांच वर्षों के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम और उनके लिए वित्तीय स्रोत;

- (झ) सम्बन्धित विद्याशाखाओं (डिप्लोमाप्लिनज) में प्रायोजक निकाय के पास उपलब्ध अनुभव और विशेषज्ञता;
- (ञ) इकाई लागत आधार पर व्यय के ब्यौरों के संदर्भ में प्रस्तावित फीस ढांचा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग छात्रों सहित आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को फीस में रियायतों या छूटों की या फीस माफी और छात्रवृत्तियों की सीमा;
- (ट) छात्रों से फीस की वसूली के माध्यम से निधियों के आन्तरिक रूप से सृजन के लिए स्कीमें, परामर्श सेवाओं और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में अन्तर्विष्ट अन्य क्रियाकलापों से प्रत्याशित राजस्व तथा अन्य प्रत्याशित आय;
- (ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;
- (ड) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;
- (ढ) यदि विश्वविद्यालय दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने का इच्छुक है, तो ऐसे अध्ययन केन्द्रों का ब्यौरा;
- (ण) यदि विश्वविद्यालय कृषकों, महिलाओं और उद्योगों के फायदे के लिए कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता है, तो उसके ब्यौरे;
- (त) खेलों, क्रीड़ा और पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध या सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित खेल मैदानों और अन्य सुविधाओं के ब्यौरे ;
- (थ) शैक्षणिक लेखा परीक्षा के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित प्रबन्ध; और
- (द) ऐसे अन्य ब्यौरे जो प्रायोजक निकाय देना चाहे ।

(3) राज्य सरकार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर ऐसे प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के परीक्षण के लिए ऐसे सदस्यों से, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मिलकर बनने वाली एक समिति का गठन करेगी, जिसमें से कम से कम विशेषज्ञ होगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा में पद "विशेषज्ञ" से उच्चतर शिक्षा के सम्बन्धित क्षेत्र (क्षेत्रों) में विख्यात विद्वान (शिक्षाविद) अभिप्रेत है ।

(4) समिति आवेदन पर निम्नलिखित आधारों पर विचार करेगी, अर्थात् :-

- (क) प्रायोजक निकाय की वित्तीय सुदृढ़ता और प्रस्तावित विश्वविद्यालय की अवसंरचना स्थापित करने की उसकी समर्थता;
- (ख) प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि अर्थात्, शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता और अनुभव, उसकी सामान्य ख्याति, तथा विनियमन निकायों के सन्निधियों का अनुसरण करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता; और
- (ग) प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सामर्थ्य अर्थात् क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम समकालीन मांगों की अपेक्षाओं के अनुसार मानव संसाधनों का विकास, राज्य की अपेक्षाओं और शिक्षा की उभरती शाखाओं में नए अवसर प्रस्तुत करने में समर्थ है ।

(5) समिति उप-धारा (4) के अधीन प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय, प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य सूचना मंगवा सकेगी जो वह उचित समझे ।

(6) समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी :

परन्तु यह कि दो मास की अवधि की संगणना करते समय, ऐसी तारीख, जिसको उप-धारा (5) के अधीन किसी सूचना के लिए अध्यपेक्षा जारी की गई है, से प्रारम्भ होने वाली और ऐसी तारीख, जिसको अपेक्षित सूचना समिति को प्रस्तुत की जाती है, को समाप्त होने वाली अवधि, अपवर्जित की जाएगी ।

आशय पत्र
का जारी
किया जाना
और
अनुपालना
रिपोर्ट ।

5. (1) धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना उचित है, तो वह प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित के लिए कहते हुए आशय पत्र जारी कर सकेगी कि वह -

- (क) धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करे;
- (ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए, और अन्य प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम दस हजार वर्ग मीटर की यथोचित आच्छादित जगह अर्जित और सन्निर्मित करे;
- (ग) कम से कम दस लाख रुपए या विनियमन निकायों के सन्निधियों के अनुसार, जो भी अधिक (उच्चतर) हो, के मूल्य की पुस्तकों और जरूरतों का, उनके अभिदान सहित, क्रय करे और प्रथम तीन वर्ष के भीतर पुस्तकालय

नेटवर्क और अन्य सुविधाओं पर तीस लाख रूपए से अन्यून या विनियमन निकायों के सन्नियमों के अनुसार, जो भी अधिक (उच्चतर) हो, व्यय उपगत करने के लिए वचन दे ताकि पुस्तकालय को पूर्ण रूप से तैयार किया जा सके और पर्याप्त सुविधाओं का उपबन्ध किया जा सके;

- (घ) सौ लाख रूपए मूल्य के या विनियमन निकायों के सन्नियमों के अनुसार, जो भी अधिक (उच्चतर) हो, के उपस्करों, कम्प्यूटरों, फर्नीचर, अन्य स्थावर (चल) और जंगम (अचल) परिसम्पत्तियों और अवसंरचना सुविधाओं [खण्ड (ख) के अधीन भवनों से अन्यथा] का क्रय करे और प्रथम पांच वर्षों के भीतर तीन सौ लाख रूपए मूल्य से अन्यून के या विनियमन निकायों के सन्नियमों के अनुसार, जो भी अधिक (उच्चतर) हो, के उपस्करों, कम्प्यूटरों, फर्नीचर, अन्य स्थावर (चल) और जंगम (अचल) परिसम्पत्तियों और अवसंरचना सुविधाएं, खण्ड (ख) के अधीन भवनों से अन्यथा; उपाप्त करने का वचन दे;
- (ङ) अध्ययन के प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व प्रत्येक विभाग या विद्याशाखा में आवश्यक सहायक स्टाफ सहित कम से कम एक आचार्य, दो सह-आचार्य और पर्याप्त संख्या में प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का वचन दे;
- (च) विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार छात्रों के फायदे के लिए सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों जैसे सेमीनारों, वाद-विवादों, प्रश्नोत्तर कार्यक्रमों और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों जैसे कि खेलों, क्रीड़ाओं, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, राष्ट्रीय कैंडेट कोर इत्यादि को चलाने के लिए वचन दे;
- (छ) भविष्य निधि की स्थापना के लिए वचन दे और कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाए;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा नियोजन में, हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को वरीयता देने के लिए वचन दे; और
- (झ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करे और ऐसी अन्य जानकारी का उपबन्ध करे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के विधि द्वारा स्थापित अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा विहित की जाएं ।

(2) प्रायोजक निकाय, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को, आशय पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करेगा और राज्य सरकार को अनुपालना रिपोर्ट देगा ।

(3) राज्य सरकार, अनुपालना रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अनुपालना रिपोर्ट का सत्यापन करने के लिए, ऐसे सदस्यों, जो अधिसूचित किए जाएं, से गठित एक समिति नियुक्त करेगी, जिसमें विनियमन निकायों का एक प्रतिनिधि भी हो और इस प्रकार नियुक्त

समिति अपने गठन की तारीख से एक मास के भीतर अपनी रिपोर्ट, राज्य सरकार को यह विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगी कि क्या प्रायोजक निकाय ने उप-धारा (1) में अधिकथित अपेक्षाएं और शर्तें पूरी कर दी हैं ।

(4) यदि प्रायोजक निकाय, उप-धारा (2) के उपबन्धों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकार हो जाएगा और उप-धारा (1) के अधीन जारी किया गया आशय-पत्र रद्द हुआ समझा जाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, प्रायोजक निकाय को तीन मास तक का और समय दे सकेगी, यदि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हो ।

विश्वविद्यालय की स्थापना । 6. (1) राज्य सरकार, यदि उसका धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबन्धों की अनुपालना कर दी है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नाम, अवस्थिति, अधिकारिता और ऐसी शर्तों के साथ, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी और अनुसूची में आवश्यक प्रविष्टियां अन्तःस्थापित कर सकेगी :

परन्तु यह कि राज्य विधान सभा के सदन द्वारा पारित संकल्प के सिवाय ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय उप-धारा (1) के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अस्तित्व में आया हुआ समझा जाएगा ।

विश्वविद्यालय का निगमन । 7. धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना । 8. विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि । 9. (1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए दो करोड़ रुपये की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया जाना है तो विन्यास निधि की रकम पचहत्तर लाख रुपये होगी ।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति से समपद्धत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा ।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखे के रूप में इस शर्त के अधधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

10. प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :-

साधारण निधि ।

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;
- (ग) परामर्शी सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;
- (घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

11. साधारण निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाएगी, अर्थात्:-

साधारण निधि का उपयोग ।

- (क) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षण तथा अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदाय, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष इत्यादि सहित ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;
- (ग) करों या स्थानीय उद्ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;
- (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उसके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;
- (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् इत्यादि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियां, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) धारा 9 और 10 के अधीन सृजित निधियों की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;
- (झ) किसी वाद या कार्यवाही, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;
- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और
- (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

विश्वविद्यालय
के अधिकारी ।

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) कुल सचिव;
- (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और
- (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

13. (1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का मुखिया होगा ।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों तथा उपाधियां, डिप्लोमें या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;
- (ख) कुलपति नियुक्त करना;
- (ग) धारा 14 की उप-धारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

14. (1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और वह उप-धारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

कुलपति

परन्तु यह कि तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी नए कुलपति के पदग्रहण करने तक पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बन्धित प्राधिकारी से उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु यह कि इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

कुल सचिव ।

15. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार/संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) कुल सचिव शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

मुख्य वित्त
तथा लेखा
अधिकारी ।

16. (1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17. (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों । अन्य अधिकारी ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

- (i) शासी निकाय;
- (ii) प्रबन्ध बोर्ड;
- (iii) विद्या परिषद्; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय
के
प्राधिकरण ।

19. (1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :- शासी निकाय ।

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;
- (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ; और
- (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना यदि वे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;
- (ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

प्रबन्ध बोर्ड ।

20. (1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलपति;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और
- (घ) अध्यापकों में से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

विद्या परिषद् ।

21. (1) विद्या परिषद् में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

22. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अन्य प्राधिकरण ।

23. कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह—

- (क) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या
- (ख) अनुमोचित दिवालिया है; या
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

24. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधि-मान्य न होना ।

25. यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नाम निर्दिष्ट करती है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए, व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

समितियां ।

26. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश के निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्रथम

परिनियम।

27. (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किए जाएं।
- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें और उसकी शक्तियां तथा कृत्य;
- (ग) कुल सचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थता के लिए प्रक्रिया;
- (छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ज) छात्रों को शिक्षा फीस (ट्यूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (झ) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से सम्बन्धित उपबन्ध;
- (ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबन्ध; और
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से सम्बन्धित उपबन्ध।

(2) प्रथम परिनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

28. (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के पश्चात्पूर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालयों के नए प्राधिकरणों का सृजन;
- (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;
- (घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;
- (ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन; और
- (झ) समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियमों से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा :

परन्तु यह कि विद्या परिषद् के परामर्श के सिवाय प्रबंध बोर्ड द्वारा छात्रों की विद्याशाखा और शिक्षण के स्तरमानों, शिक्षा और परीक्षा को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को नहीं बनाया जाएगा ।

प्रथम 29. (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यादेश । उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबन्ध बोर्ड ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में उपबंध;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और
- (ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जाने अपेक्षित हों ।

(2) प्रबंध बोर्ड या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ

अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. (1) प्रथम अध्यादेशों से भिन्न समस्त अध्यादेश विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

पश्चात्कर्ती
अध्यादेश ।

(2) विद्या परिषद् प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों अध्यादेशों को वापिस भेजेगी और प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगा और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधधीन विनियम । रहते हुए उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारवार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

32. (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किया प्रवेश । जाएगा :

परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कोटा भरने के प्रयोजन के लिए योग्यता के अवधारण हेतु आकलन सीमा (जोन आफ कन्सिडरेशन) मात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों तक ही सीमित होगी ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो प्रवेश के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ की और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकती है :

परन्तु यह कि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और महिलाओं और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्थान राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे।

फीस संरचना । 33. (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार और पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के दो मास के भीतर अनुमोदन प्रदान करेगी :

परन्तु यदि सरकार दो मास के भीतर अनुमोदन प्रदान नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(2) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस ;

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात :-

- (i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और
- (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी।

परीक्षाएं । 34. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलेंडर वर्ष के 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात (अपश्चात) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

स्पष्टीकरण :- "परीक्षाओं की अनुसूची" से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरे देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है तो वह यथासाध्य शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा । परिणामों की घोषणा ।

परन्तु यह कि किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम केवल इस कारण से अविधिमन्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 और 35 में यथानियत परीक्षा की अनुरूची का पालन नहीं किया है ।

36. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, दीक्षांत डिप्लोमें प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिणियमों द्वारा यथा विहित रीति समारोह । से आयोजित किया जाएगा ।

37. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.), बंगलौर विश्वविद्यालय से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार और ऐसे का अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, प्रत्यायन । राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

38. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों इत्यादि का अनुपालन करने के द्वारा विनियमन करने वाले लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित निकायों के हों । नियमों, विनियमों, सन्नियमों इत्यादि का अनुसरण ।

39. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी वार्षिक जिसमें अन्य बातों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए रिपोर्ट । कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा । 40. (1) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित, वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत, सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा जो यह उचित समझे और उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां । 41. (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय से सम्बन्धित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार कुलपति से परामर्श के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जैसा यह उचित समझे निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) में दी गई सिफारिश का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन । 42. (1) प्रायोजक निकाय सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे ।

43. (1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का अतिक्रमण किया है या धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन नहीं किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह विश्वविद्यालय को, पैतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां ।

(2) यदि सरकार का उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अतिक्रमण का, या धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन दिए गए परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो, वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जैसा वह अवश्यक समझे ।

(3) सरकार, उप-धारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही 1908 का 5 शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों 1974 का को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(6) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का अतिक्रमण किया है, या धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए परिवर्धनों का पालन नहीं किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और वह इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड के सभी कर्तव्यों के अध्यक्षीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उप-धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा और ऐसी तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे ।

नियम बनाने
की शक्ति ।

44. (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:-

- (क) विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करने की रीति और धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन संदेय फीस;
- (ख) धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;
- (ग) धारा 43 की उप-धारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ; और
- (घ) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधानमण्डल ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

“अनुसूची”

(धारा 6 देखें)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम और अवस्थिति	विश्वविद्यालय की अधिकारिता
1	2	3

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के बहुमुखी विकास में महत्वापूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं। विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों इत्यादि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है।

देश में अन्य राज्यों की तरह, सोसाइटियों/प्राइवेट सेक्टर, विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव कर रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार को ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक पृथक् मामले में अन्यथा विधान लाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार एक बहुप्रयोजनीय विधान लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने का उपबन्ध करेगा। यह प्रत्येक नए विश्वविद्यालय के लिए पृथक् विधान लाने की आवश्यकता का निवारण करेगा। इसके साथ-साथ यह राज्य विधान मण्डल का उसकी यथोचित भूमिका से यह अपेक्षा करते हुए कि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की अधिसूचना केवल राज्य विधान मण्डल द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात् ही जारी की जाएगी, अपनयन नहीं करेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक विधान अर्थात् हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2006 लाने का विनिश्चय किया गया है जो "आशय-पत्र" जारी करने से पूर्व पक्षकार की विशेषज्ञता, वित्तीय स्थिति और उसकी पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल करने में समर्थ बनाएगा और विश्वविद्यालय को अधिसूचित करने का अन्तिम कदम अपेक्षित सुविधाओं के सृजन और उपगत व्यय की बाबत एक और रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ही उठाया जाएगा। बारम्बार पड़ताल की यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अच्छी वित्तीय स्थिति वाले, अनुभवी और प्रतिबद्ध पक्षकार ही अन्तिम चरण, अर्थात् विश्वविद्यालय की अधिसूचना, तक पहुंचें।

यह विधेयक इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालय से, विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा करने का उपबन्ध भी करता है और कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने तथा इसके साथ-साथ प्रबन्धन को पर्याप्त स्वतन्त्रता देने का भी उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**वीरमद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।**

शिमला :

तारीख.....2006.

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में केवल प्राइवेट सेक्टर में ही प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्भूत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 44 और 27 (2) राज्य सरकार को क्रमशः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम बनाने के लिए और सशक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 28 (2) और 29 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को क्रमशः विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम और अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2006

राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने और उनके क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला

तारीख.....2006.

BILL No. 7 of 2006

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of private universities in the State for higher education and to regulate their functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2006.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) “Board of Management” means the Board of Management constituted under section 20;
- (b) “campus” means the area of university within which it is established;
- (c) “distance education” means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

- (d) "employee" means any person appointed by the university and includes teachers and other staff of the university;
- (e) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 19;
- (f) "fee" means monetary collection made by the university or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;
- (g) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
- (i) "hostel" means a place of residence for the students of the university, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the university;
- (j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (k) "off campus centre" means a centre of the university established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the university's complement of facilities, faculty and staff;
- (l) "Official Gazette" means the Rajpatra of Himachal Pradesh;
- (m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grant Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Indian Research etc. and includes the Government;
- (o) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;
- (p) "section" means a section of this Act;
- (q) "sponsoring body" means a body desirous of setting up a university which may be,—
 - (i) a Society registered under the Societies Registration Act, 1860; or 21 of 1860
 - (ii) any Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 or under the relevant laws in any other State or Union Territory; or 2 of 1882
 - (iii) a company registered under the Companies Act, 1956; 1 of 1956
- (r) "State" means State of Himachal Pradesh;

- (s) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the university made under this Act;
- (t) "student" means a person enrolled in the university for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the university, including a research degree;
- (u) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the university for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;
- (v) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the university; and
- (w) "university" means a university established and incorporated under this Act.

3. The objects of a University shall include,—

The objects
of the
university.

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;
- (b) to establish facilities for education and training;
- (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;
- (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;
- (e) to establish campus in the State;
- (f) to establish examination centres;
- (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the university shall ensure

that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

- (h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

Submission
of proposal
for
establish-
ment
of a
university
and its
evaluation.

4. (1) An application containing proposals and the project report to establish a university in the private sector shall be made by the sponsoring body to the Government, alongwith such fee as may be prescribed.

(2) The project report shall contain the following particulars, namely : —

- (a) the details of the sponsoring body alongwith the copies of its registration certificate, constitution and bye-laws;
- (b) the information regarding financial resources of the sponsoring body alongwith latest audited accounts;
- (c) the name, location, areas of operation and headquarters of the proposed university;
- (d) the objectives of the university;
- (e) justification regarding the necessity of establishment of the proposed university;
- (f) the nature and courses of study with course-wise enrolment targets and research proposed to be undertaken by the university and their relevance to the development goals and local needs of the State and phasing of such programmes over the first five years;
- (g) the details of land/buildings and infrastructure facilities required by the university and means of acquiring the same;
- (h) the details of plans for campus development such as construction of buildings, infrastructure facilities and other amenities, procurement of equipment, etc. to be undertaken before the university starts functioning and phased programme for first five years and sources of finance for the same;
- (i) the experience and expertise in the concerned disciplines available with the sponsoring body;
- (j) the proposed fee structure with reference to the details of expenditure on unit cost basis and the extent of concessions or rebates in fees or free-ships and scholarships proposed for students from economically or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and handicapped students;
- (k) the schemes for the generation of funds internally through fees from students, revenues anticipated from consultancy

- services and other activities included in the objects of the university and other anticipated income;
- (l) the system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the university;
 - (m) the system proposed to be followed for appointment of employees in the university;
 - (n) if the university is desirous of taking up distance education programmes, details of such study centres;
 - (o) if the university proposes to start programmes for the benefit of farmers, women and industries, details thereof;
 - (p) details of playgrounds and other facilities available or proposed to be created for games, sports and extra curricular activities;
 - (q) the arrangements proposed to be made for academic auditing; and
 - (r) any other details as the sponsoring body may like to give.

(3) The Government, on receipt of an application complete in all respect, shall constitute a committee consisting of such members as may be specified in the notification published in the Official Gazette, out of whom at least one shall be an expert, to examine the proposals so submitted.

Explanation.—In this sub-section the expression “expert” means an academician of eminence in the respective field(s) of higher education.

(4) The committee shall consider the application on the following grounds, namely :—

- (a) financial soundness of the sponsoring body and its ability to set up the infrastructure of the proposed university;
- (b) back ground of the sponsoring body *i.e.* its expertise and experience in the field of education, its general reputation, and its commitment to follow the norms of the regulating bodies; and
- (c) potentiality of the courses proposed to be offered that is to say whether the courses proposed would be able to develop human resources as per the requirements of contemporary demands, offer new opportunities in emerging branches of education and the requirements of the State.

(5) The committee, while considering the proposal and the project report under sub-section (4), may call for such other information from the sponsoring body as it thinks proper.

(6) The committee shall submit its report to the Government within a period of two months from the date of its constitution :

Provided that while computing the period of two months, the period commencing from the date on which requisition for any information under sub-section (5) is issued and ending on the date on which requisite information is submitted to the committee, shall be excluded.

Issuance of
the letter of
intent and
compliance
report.

5. (1) After the receipt of the report of the committee constituted under sub-section (3) of section 4, if the Government is satisfied that it is advisable to establish the university, it may issue a letter of intent asking the sponsoring body to—

- (a) establish an endowment fund in accordance with the provisions of section 9;
- (b) acquire and construct a minimum of 10,000 square meters of covered space suitable for conducting academic programmes, and for other purposes;
- (c) purchase books and journals, including subscription thereof, at least worth ten lacs rupees or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher, and give an undertaking to incur expenditure for library networking and other facilities so as to well equip the library and to provide adequate facilities within first three years which shall not be less than thirty lacs rupees or as per the norms of regulating body, whichever is higher;
- (d) purchase equipments, computers, furniture, other moveable and immovable assets and infrastructure facilities [(except buildings, under clause (b)] worth one hundred lacs rupees or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher, and give an undertaking to procure within the first five years equipments, computers, furniture, other movable and immovable assets and infrastructure facilities other than buildings, under clause (b) worth not less than three hundred lacs rupees or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher;
- (e) give an undertaking to appoint at least one Professor, two Associate Professors and adequate number of Lecturers alongwith necessary supporting staff in each department or discipline atleast one month before commencement of studies;
- (f) give an undertaking to take up co-curricular activities like seminars, debates, quiz programmes and extra-curricular activities like games, sports, National Service Scheme,

National Cadet Corps, etc. for the benefit of students as per the norms laid down by the regulating bodies;

- (g) give an undertaking for the establishment of provident fund and to take up welfare programmes for the employees;
- (h) give an undertaking to give preference to bonafide residents of Himachal Pradesh in the employment by the university; and
- (i) fulfil such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the University Grants Commission, All India Council for Technical Education or any other statutory body established by the law of the Central or the State Government.

(2) The sponsoring body shall fulfil the requirements and conditions specified in sub-section (1) within a period of one year from the date of issue of letter of intent and report compliance to the Government.

(3) On receiving the compliance report, the Government shall appoint a committee consisting of such members, including a representative of the regulating bodies, as may be notified, to verify the compliance report and the committee, so appointed, shall submit its report to the Government within one month from the date of its constitution specifying whether the sponsoring body has fulfilled the requirements and conditions laid down in sub-section (1).

(4) If the sponsoring body fails to comply with the provisions of sub-section (2), its proposal shall stand rejected and the letter of intent issued under sub-section (1) shall stand cancelled :

Provided that the Government may further extend the time upto three months to the sponsoring body if there exists sufficient reasons for the delay.

6. (1) The Government, if satisfied, after considering the report submitted under sub-section (3) of section 5 that the sponsoring body has complied with the provisions of sub-section (1) of section 5, may by notification in the Official Gazette, establish a university with such name, location, jurisdiction and with such conditions as may be specified in such notification and insert necessary entries in the Schedule :

Establishment of the university.

Provided that, no such notification shall be issued except on a resolution passed by the House of the State Legislature.

(2) The university shall come into existence from the date of publication of the notification in the Official Gazette under sub-section (1).

Incorporation of the university.

7. Every university established under sub-section (1) of section 6 shall be a body corporate by the name notified, having perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.

University to be self-financed.

8. The university shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

Endowment Fund.

9. (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the university with an amount of two crore rupees which shall be pledged to the Government :

Provided that if the university is to be established in a tribal area, the amount of Endowment Fund shall be seventy five lacs rupees.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the university or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilised for the development of infrastructure of the university but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the university.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the university, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

General Fund.

10. Every university shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

- (a) fees and other charges received by the university;
- (b) any contribution made by the sponsoring body;
- (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the university;
- (d) bequests, donations, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the university.

11. The General Fund shall be utilized for the following purposes,
namely :—

Application
of General
Fund.

- (a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the university and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;
- (b) for the expenses to be incurred by the university for services availed including services like electricity, telephone etc.;
- (c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;
- (d) for up keeping of the assets of the university;
- (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the university;
- (f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, etc. ;
- (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;
- (h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 9 and 10;
- (i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which university is a party;
- (j) for the purpose of movable and immovable assets;
- (k) for the payment of any expenses incurred by the university in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and
- (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the university :

Provided that no expenditure shall be incurred by the university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

Officers of
the
university.

12. The following shall be the officers of the university, namely:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (v) such other persons in the service of the university as may be declared by the statutes to be the officers of the university.

The
Chancellor.

13. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the university.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the university for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

- (a) to call for any information or record;
- (b) to appoint the Vice-Chancellor;
- (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 14;
- (d) such other powers as may be specified by the statutes.

The Vice-
Chancellor.

14. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that, after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that a Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-chancellor joins; however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the university and shall have the general superintendence and control over the affairs of the university and shall execute the decisions of various authorities of the university.

(3) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the university in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter :

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the university is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the university, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If, at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-chancellor is not in the interests of the university, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order :

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

15. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

The
Registrar.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement/contract, sign documents and authenticate records on behalf of the university and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

The Chief
Finance and
Accounts
Officer.

16. (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

Other
officers.

17. (1) The university may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the university and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

Authorities
of the
university.

18. The following shall be the authorities of the university, namely:—

- (i) the Governing Body;
- (ii) the Board of Management;
- (iii) the Academic Council; and
- (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the university.

The
Governing
Body.

19. (1) The Governing Body of the university shall consist of the following, namely:—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;
- (d) one expert of management or information technology from outside the university, nominated by the Chancellor; and
- (e) two persons, nominated by the Government.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the university.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the university by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made there under;
- (b) to review the decisions of other authorities of the university in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
- (c) to approve the budget and annual report of the university;
- (d) to lay down the policies to be followed by the university;
- (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the university if a situation arises when smooth functioning of the university does not remain possible, in spite of all efforts; and
- (f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

20. (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

The Board
of Manage-
ment.

- (a) the Vice-chancellor;
- (b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
- (c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and
- (d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

The
Academic
Council.

21. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the university and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the university.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

Other
authorities.

22. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the university shall be such as may be specified by the statutes.

Disquali-
fications.

23. A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the university, if he

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
- (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
- (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

Vacancies
not to
invalidate
the proce-
edings of
any authori-
ty or body
of the
university.

24. No act or proceeding of any authority or body of the university shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling of
casual
vacancies.

25. In case there occurs any casual vacancy of any member in any authority or body of the university, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

26. (1) The authorities or officers of the university may constitute Committees committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

27. (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First statutes of the university may provide for all or any of the following matters, namely: The First statutes.

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the university as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;
- (d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;
- (e) the terms and conditions of service of employees of the university;
- (f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the university;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
- (i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
- (j) provisions regarding fees to be charged from the students; and
- (k) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The First statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette, and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

28. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the university may provide for all or any of the following matters, namely:— The Subsequent statutes.

- (a) creation of new authorities of the university;
- (b) accounting policy and financial procedure;

- (c) representation of teachers in the authorities of the university;
- (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation of posts and procedure for abolition of posts;
- (g) revision of fees;
- (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and
- (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the university other than the First statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section :

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the university until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government :

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

The First
ordinances.

29. (1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such First ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the university and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the admission of students to the university and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the university;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same

and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

- (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the university;
- (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the university;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the university;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education;
- (k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the university with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. (1) All ordinances other than the First ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

The Subsequent ordinances.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the university with or without such

modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

Regulations.

31. The authorities of the university may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

Admissions.

32. (1) Admission in the university shall be made strictly on the basis of merit :

Provided that for the purpose of filling minority quota in the university established and administered by minority community, zone of consideration for determination of merit shall be limited only to the students belonging to that minority community.

(2) Merit for admission in the university may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the universities conducting similar courses or by any agency of the State :

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the university, for the students belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes and women and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

Fee structure.

33. (1) The university may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within two months from the receipt of the proposal :

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within two months, it shall be deemed to have been approved by the Government.

(2) The Government shall consider the fees structure prepared by the university and if it is satisfied that the proposed fees is,—

(a) sufficient for generating—

- (i) resources for meeting the recurring expenditure of the university; and
- (ii) the savings required for the further development of the university; and

(b) not unreasonably excessive,
it may approve the fee structure.

(3) The fee structure approved by the Government under sub-section (2) shall remain valid until next revision.

34. At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the university shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such schedule.

Examinations.

Explanation.—"Schedule of Examination" means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations :

Provided that if, for any reason whatsoever, university is unable to follow this schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

35. (1) The university shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date :

Declaration
of results.

Provided that if, for any reason whatsoever, the university is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the university has not followed the Schedule of Examination as stipulated in sections 34 and 35.

Convocation.

36. The convocation of the university shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

Accreditation
of the
university.

37. The university shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the university about the grade provided by NAAC to the university and the university shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

University
to follow
rules, regu-
lations,
norms etc.
of the regu-
lating bodies.

38. Notwithstanding anything contained in this Act, the university shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

Annual
report.

39. (1) The annual report of the university shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the university towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

Annual
accounts
and audit.

40. (1) The annual accounts including balance sheet of the university shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the university for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance-sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the university shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

41. (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the university, the Government may, after consultation with the Vice-Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

Powers of the Government to inspect the university.

(2) The Government shall communicate to the university its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the university shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the university fails to comply with the recommendation made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the university.

42. (1) The sponsoring body may dissolve the university by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the university at least one year in advance :

Dissolution of the university by the sponsoring body.

Provided that dissolution of the university shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the university all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body.

43. (1) If it appears to the Government that the university has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given under sub-section (1) of section 5 or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the university, it shall issue notice requiring the university to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

Special powers of the Government in certain circumstances.

(2) If the Government, on receipt of reply of the university on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made there under or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given under sub-section (1) of section 5 or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
- (c) requisitioning any public record from any court or office; and
- (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section (3), if the Government is satisfied that the university has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it under sub-section (1) of section 5 or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the university which threatens the academic standard of the university, it shall issue orders for the liquidation of the university and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the university until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to the effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the university and from the date of publication of such notification,

the university shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body from such date.

44. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power to
make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the manner of making proposal to establish a university and the fees payable under sub-section (1) of section 4;
- (b) other particulars to be contained in the project report under sub-section (2) of section 4;
- (c) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 43; and
- (d) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

45. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to
remove
difficulties.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

SCHEDULE

(See section 6)

Sl. No.	Name and location of the university	Jurisdiction of the university
1	2	3

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges/Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, societies/the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Establishment of such private Universities would otherwise require legislation in each individual case. As such, there is an urgent need to bring an omnibus legislation which would provide for establishment, incorporation and regulation of private Universities in the State for higher education. It will obviate the need to have separate legislation for each new University. At the same time, it does not remove the State's Legislature from its due role by requiring that the notification establishing a University is issued only after a resolution is passed by the State's Legislature.

Keeping in view the above, it has been decided to bring a legislation *i.e.* the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2006 which will enable checking the expertise, the financial position and the background of the party before issue of "letter of intent" and final step of notifying an University will be taken only after obtaining another report about the creation of required facilities and expenditure incurred. This system of repeated checks will ensure that only financially sound, experienced and committed parties reach the final stage *i.e.* the notification of an University. The Bill further provides for requiring the proposed University to obtain approval from regulatory authorities and also provides for intervention of the State Government in certain circumstances while at the same time giving considerable freedom to the management.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The _____ 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of Private Universities in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure on the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 44 and 27(2) of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make First statutes of the University respectively. Further clauses 28 (2) and 29 of the Bill seeks to empower Board of Management of the university to make subsequent statutes and ordinances of the university respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) BILL, 2006**

A

BILL

*to provide for establishment, incorporation and regulation of private Universities in the State
for higher education and to regulate their functioning and for matters connected
therewith or incidental thereto.*

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law)

SHIMLA:

The _____ 2006.